THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT (SHRI P.K. THUNGON): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

स्वयंसेवी संगठनों द्वारा अनुदानों का दुरुपयोग

1279. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि स्वयंसेवी संगठनों द्वारा अनुदानों का दुरुपयोग किए जाने के बाद सरकार द्वारा उन्हें प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता ही रोकी जाती है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन कानूनों के तहत ऐसे संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कानूनों के तहत कितने संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई और उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग में और संस्कृति विभाग में) उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) योजनाओं में सामान्यतः गैर सरकारी संगठनों की संस्वीकृति-पूर्व संवीक्षा करने का प्रावधान है। संस्वीकृति और उत्तरवर्ती अनुवीक्षण के पूर्व विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु अंतर्निर्मित व्यवस्थाएं हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र और राज्य एजेंसियों द्वारा निरीक्षण का प्रावधान है तथा नया अनुदान प्रदान करने के पूर्व पहले जारी किये गये अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र की मांग की जाती है तथा गैर-सरकारी संगठन का कार्य-निष्पादन संतोषजनक न पाए जाने पर वित्तीय सहायता रोक दी जाती है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Development of Agriculture Sector in North East

1280. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the details of various programmes/ schemes initiated by Government to develop agriculture sector in the North East Region;

(b) how far these have helped the development of agriculture in the Region; and

(c) the strategy being adopted in the Eighth Five Year Plan in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) Important programmes implemented by the Government of India for the development of agriculture in the North East region include Integrated Cereals Development Programme in Rice based cropping system's Area, Special Jute Development Programme, Oilseeds Development Programme, National Pulses Development Project, National Watershed Development Project for Rainfed Areas, Watershed Development in Shifting Cultivation Areas, Development Programmes for Spices, Fruits, Vegetables, Cashewnut, Coconut and other horticultural crops, Integrated Pest Management Development, etc.

(b) The schemes have helped in improving and productivity of foodgrains and other crops in these States in recent years.

(c) The strategy for development of agriculture in N.E. States includes improvement in productivity of crops, diversification of agriculture and promotion of horticultural crops and fisheries.

Implementation of Government Orders Withholding Closure of Stationery Offices

1281. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government of India's order dated 27th February, 1991, withholding the order of closure of Stationery Offices, has since been implementated;

(b) if not, the reasons thereof;

(c) whether it is also a fact that Government have transferred paper purchasing authority to Director of Printing from Stationery Department; and

(d) if so, whether the above mentioned transfer of paper purchasing authority is in accordance with General Financial Rules, 1963?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT (SHRI P.K. THUNGON): (a) and (b) The procurement and distribution of stationery items by the Government of India Stationery Office, Calcutta and its three Regional Stationery Depots at New Delhi, Bombay and Madras, have been resumed.

(c) and (d) The ad hoc purchase of printing paper, in respect of which there is no rate-contract, has been delegated to the Directorate of Printing, consequent upon decentralisation of the activities of the Directorate General of Supplies & Disposals. Wherever rate contracts of the Directorate General of Supplies and Disposals exist, purchase continues to be made through them. As such there is no violation of the General Financial Rules, 1963.

Cases of Cheating by the Builders

1282. DR. RANBIR SINGH: Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether some builders tempt the people by their false lucrative advertisements to book flats with them and thereafter cheat the buyers of their money by dishonouring the terms agreements;

(b) if so, how many such cases have come to light during the last three years in Delhi and the details of the modus operandi adopted by such builders, to cheat the public; and

(c) what action has been taken by Government against such unscrupulous builders and what steps have been taken to safeguard the interests of the public?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT (SHRI P.K. THUNGON): (a) to (c) The information is being colected and will be laid on the Table of the Sabha.

सामाजिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता

1283. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, बाल-आश्रमों, महिला-आश्रमों और विकास-गृहों को केन्द्रीय कोष से वर्ष-वार और जिला-वार कितनी-कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ इन संस्थाओं को पूर्ण रूप से मिल रहा है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं का समय-समय पर अध्ययन किया जा रहा है और यदि हां, तो क्या-क्या खूबियां/त्रुटियां सामने आई हैं;

(घ) केन्द्रीय कोष से प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता के आंवटन/वितरण के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य-वार कितना प्रावधान किया जाता है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी): (क) सामाजिक संगठनों को वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा अनेक मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से दी जाती है। इस प्रकार के अनुदान का ब्यौरा एक स्थान पर नहीं रखा जाता। तथापि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों में इस प्रकार के प्रमुख अनुदानों का ब्यौरा होता है। ये वार्षिक रिपोर्ट संसद के माननीय सदस्यों को भेजी जाती हैं और संसद के पुस्तकालय में भी रखी जाती हैं। फिर भी, पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्मुक्त अनुदान का ब्यौरा विवरण में दिया गया है । (नीचे देखिये)

(ख) स्कीमों का पूरा लाभ लाभार्थियों तक पहुंचे यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार बिभिन्न उपाय करती है। स्कीमों के कार्यान्वयन का प्रबोधन आवधिक